in cost at the lowest level and the substantial tax liability at the highest level. It has also been the policy of the Government to encourage workers' participation in management to bring about a greater involvement of workers with the management. Government is also engaged in the formulation of the basic principles of a National wage policy which is intended to be finalised in consultation with the representatives of employers, workers and other interests concerned at the next tripartite labour conference.

सरकार को राजस्थान में खनिजों से अर्जित राजस्व

5005. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सिरोही और जालौर जिलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध खनिजों से सरकार द्वारा कितना राजस्व कमाया जाता है और उस पर कितना व्यय होता है ; और

(ख) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान बड़ी मात्रा में खनिजों के मिलने की कोई सम्भावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : (क) राज्य सरकार के खान तथा भूतत्व विभाग द्वारा सिरोही और जालौर जिलों में खनिजों से रायल्टी तथा लगान के रूप में अर्जित राजस्व राशि 1980-81 वर्ष में 11.19 लाख रुपये तथा अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक 4.90 लाख रुपये थी । 1980-81 के दौरान किया गया व्यय 6.64 लाख रुपये तथा अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक 4.02 लाख रुपये था ।

(ख) वर्ष 1982-83 में सिरोही तथा जालौर जिलों में खनिज मिलने की सम्भावनायें मौजूद हैं लेकिन यह बताना सम्भव नहीं है कि प्राप्त खनिज बड़ी मात्रा में होंगे । राज्य के खान विभाग तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए टोही कार्य और खनिज खोज कार्य को देखते हुए 1982-83 के दौरान टंगस्टन तांबा तथा चूना पत्थर के और निक्षेप पाए जाने की सम्भावना है ।

बम्बई तथा दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों हेतु सरकारी आवास

5006. **श्री निहाल सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग आयोग मुख्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें क्वार्टरों का आबंटन किया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें मकान किराये भत्ते का भुगतान किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एक स्वायत्तशासी संगठन है, इस लिए इसके कर्मचारी सरकारी आवास प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं । किन्तु आयोग ने बम्बई में लगभग 205 क्वार्टरों का अधिग्रहण किया है तथा 32 और क्वार्टरों का अधिग्रहण शीघ्र ही कर लिये जाने की सम्भावना है । दिल्ली में, आवास किराये पर ले लिया गया है और आयोग के दो कर्मचारियों को इनका आबंटन कर दिया गया है । इस समय बम्बई और दिल्ली में कुल मिलाकर 204 व्यक्तियों को क्वार्टर दिए गए हैं । आयोग के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की किराया भत्ता दर पर आवास किराया भत्ते के पात्र हैं । निधियों के अभाव के कारण मांग के अनुरूप क्वार्टर दे पाना सम्भव नहीं है ।